VIDYA BHAWAN BALIKA VIDYA PITH

शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय बिहार

class 12 commerce Sub. ECO/ B Date 2.6.2020

Teacher name – Ajay Kumar Sharma

INDIAN ECONOMY 1950–1990

Question 15:

Why, despite the implementation of green revolution, 65 per cent of our population continued to be engaged in the agriculture sector till 1990?

ANSWER:

Although Indian agricultural production increased substantially that enabled India to attain the status of self-sufficiency in food grains but this increase is substantial only in comparison to food grain production in the past. Further, India failed to achieve structural transformation associated with the agricultural revolution and development. That is, in other words, industrial and service sector failed to generate significant employment opportunities in order to attract and absorb excess agricultural labour. The agricultural contribution to GDP has fallen from 51% in 1960-61 to 44% in 1970-71, on the other hand, the share of industry and service sector in India's GDP increased merely from 19% to 23% and from 30% to 33% during the same period. Meantime, the percentage of population dependent on agriculture decreased merely from 67.50% (in 1950) to 64.9% (in 1990). Hence, the industrial and service sector growth was not very significant and, hence, failed to employ and attract surplus labour from agricultural sector. This may be because of the flaws in the economic policies that became the bottleneck for the growth of secondary and tertiary sector.

यद्यपि भारतीय कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिसने भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाया, लेकिन यह वृद्धि केवल खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में पर्याप्त है। इसके अलावा, भारत कृषि क्रांति और विकास से जुड़े संरचनात्मक परिवर्तन को प्राप्त करने में विफल रहा। अर्थात्, दूसरे शब्दों में, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र, अतिरिक्त कृषि श्रम को आकर्षित करने और अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में विफल रहे। जीडीपी में कृषि योगदान 1960-61 में 51% से घटकर 1970-71 में 44% हो गया, दूसरी ओर, भारत की जीडीपी में उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल 19% से बढ़कर 23% और 30% से बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान 33%। इस बीच, कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत केवल 67.50% (1950 में) से घटकर 64.9% (1990 में) हो गया। इसलिए,

औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी और इसलिए, कृषि क्षेत्र से अधिशेष श्रम को रोजगार और आकर्षित करने में विफल रहा। इसका कारण यह हो सकता है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि के लिए अड़चन बन गई आर्थिक नीतियों में खामियां

Question 16:

Though public sector is very essential for industries, many public sector undertakings incur huge losses and are a drain on the economy's resources. Discuss the usefulness of public sector undertakings in the light of this fact.

ANSWER:

Although, the mismanagement and wrong planning in PSUs may lead to misallocation and, consequently, to wastage of the scarce resources and finance but PSUs do have some positive and useful advantages.

1. *Enhancing Nation's Welfare*: The main motive of the PSU was to provide goods and services that add to the welfare of the country as a whole. For example, schools, hospitals, electricity, etc. These services not only enhance welfare of country's population but also enhance the future prospects of economic growth and development.

2. *Long Gestation Projects*: It was not feasible and economically viable for the private sectors to invest in the big and wide projects like basic industries and electricity, railways, roads, etc. This is because these projects need a very huge initial investment and have long gestation period. Hence, PSU is the most appropriate to invest in these projects.

3. *Basic Framework*: An important ideology that was inherited in the initial five year plans was that the public sector should lay down the basic framework for industrialisation that would encourage the private sector at the latter stage of industrialisation.

4. *Socialist Track*: In the initial years after independence, Indian planners and thinkers were more inclined towards socialist pattern. It was justified on the rational ground that if the government controls the productive resources and production, then it won't mislead the country's economic growth. This was the basic rationale to set up PSUs. These PSUs produce goods not according to the price signals but according to the social needs and economic welfare growth of the country.

5. *Reduce Inequality of Income and Generate Employment Opportunities*: It was assumed that in order to reduce inequalities of income, eradicate poverty and to raise the standard of living, government sector should invest in the economy via PSUs.

हालांकि, सार्वजनिक उपक्रमों में कुप्रबंधन और गलत योजना के कारण दुराचार हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप, दुर्लभ संसाधनों और वित्त का अपव्यय होता है लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ सकारात्मक और उपयोगी फायदे हैं।

1. राष्ट्र के कल्याण को बढ़ाना: पीएसयू का मुख्य उद्देश्य उन वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करना था जो पूरे देश के कल्याण में जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल, अस्पताल, बिजली आदि, ये सेवाएँ न केवल देश की आबादी के कल्याण को बढ़ाती हैं, बल्कि आर्थिक विकास और विकास की भावी संभावनाओं को भी बढ़ाती हैं।

2. लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स: निजी क्षेत्रों के लिए बुनियादी उद्योगों और बिजली, रेलवे, सड़क आदि जैसी बड़ी और व्यापक परियोजनाओं में निवेश करने के लिए यह संभव नहीं था और आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए बहुत बड़े प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है और लंबे गर्भकाल की अवधि। इसलिए, पीएसयू इन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है।

3. बुनियादी ढांचा: एक महत्वपूर्ण विचारधारा जो आरंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में विरासत में मिली थी, वह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिकीकरण के लिए बुनियादी ढाँचे को रखना चाहिए जो औद्योगिकीकरण के बाद के चरण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा।

4. समाजवादी ट्रैक: स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में, भारतीय योजनाकारों और विचारकों का झुकाव समाजवादी पैटर्न की ओर अधिक था। यह तर्कसंगत आधार पर उचित था कि यदि सरकार उत्पादक संसाधनों और उत्पादन को नियंत्रित करती है, तो यह देश की आर्थिक वृद्धि को भ्रमित नहीं करेगा। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के लिए यह मूल तर्क था। ये सार्वजनिक उपक्रम मूल्य संकेतों के अनुसार नहीं बल्कि देश की सामाजिक आवश्यकताओं और आर्थिक कल्याण वृद्धि के अनुसार माल का उत्पादन करते हैं।

5. आय की असमानता को कम करना और रोजगार के अवसर पैदा करना: यह माना गया था कि आय की असमानताओं को कम करने के लिए, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, सरकारी क्षेत्र को पीएसयू के माध्यम से अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहिए।